(June2025). वर्तमान परिप्रेक्ष्य व बांग्लादेश मे सत्ता परिवर्तन
International Journal of Economic Perspectives,*19*(06) 60-64
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

वर्तमान परिप्रेक्ष्य व बांग्लादेश मे सत्ता परिवर्तन

राकेश कुमार
शोधार्थी (राजनीति विज्ञान)
महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

डॉ. नूरजहाँ
सह–आचार्य (राजनीति विज्ञान)
राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर

सारांश

अगस्त 2024 का महीना बांग्लादेश के इतिहास में एक नए लोकतांत्रिक अध्याय की शुरुआत के रूप में दर्ज हुआ है। ढाका विश्वविद्यालय से प्रारंभ हुआ "कोटा आरक्षण विरोधी आंदोलन" शीघ्र ही एक व्यापक जनआंदोलन में बदल गया, जिसने शेख हसीना की 16 वर्षीय सत्तावादी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इस आंदोलन ने बांग्लादेश के नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं को लोकतंत्र, मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में एकजुट किया। आंदोलन के परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसने लोकतांत्रिक संस्थाओं की पुनर्बहाली और निष्पक्ष चुनाव कराने का आश्वासन दिया।

हालाँकि, यह परिवर्तन पूरी तरह शांतिपूर्ण नहीं था–अल्पसंख्यकों पर हमले, धार्मिक कट्टरपंथी संगठनों की सक्रियता और प्रशासनिक अस्थिरता जैसी चुनौतियाँ सामने आईं। इन परिस्थितियों में बांग्लादेश के भविष्य की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि क्या उसकी नई राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बना पाएगी या नहीं।

भारत के लिए यह सत्ता परिवर्तन रणनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है। हसीना सरकार, जो भारत की प्रमुख सहयोगी थी, के पतन के बाद भारत–बांग्लादेश संबंधों में अस्थिरता देखी जा रही है। अंतरिम सरकार का झुकाव अमेरिका की ओर अधिक दिखाई देता है, जबकि पाकिस्तान और चीन भी अपनी भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत को अब अपने पड़ोसी देश के साथ संबंधों में नई नीतिगत दिशा तय करनी होगी, ताकि दक्षिण एशिया में संतुलन और स्थिरता बनी रहे।

सारांशतः, बांग्लादेश का हालिया घटनाक्रम लोकतंत्र, मानवाधिकार, और शासन व्यवस्था के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का प्रतीक है, जिसका क्षेत्रीय राजनीति और भारत की विदेश नीति पर गहरा प्रभाव पड़ना निश्चित है।

मुख्य शब्द– बांग्लादेश, सत्ता परिवर्तन, लोकतंत्र बहाली, शेख हसीना, मोहम्मद यूनुस, कोटा आंदोलन, मानवाधिकार, अंतरिम सरकार, राजनीतिक अस्थिरता, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, कूटनीतिक प्रभाव, युवाशक्ति आंदोलन, विरोध आंदोलन, शासन व्यवस्था पुनर्निर्माण।

प्रस्तावना

अगस्त का घटनाक्रम बांग्लादेश के इतिहास का महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक स्वतंत्रता में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा याद किया जाएगा जो ढाका यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ कोटा आरक्षण एक लोकतांत्रिक व्यवस्था परिवर्तन बदल गया जिसमें समाज के सभी वर्गों में प्रमुख विपक्षी दलों ने मिलकर एक विजयपूर्ण लड़ाई लडी है इसमें प्रमुख आंदोलनकारी की विचारधारा के अनुसार– हम एक निष्पक्ष मूल्यांकन चाहते हैं वे न तो भारत के प्रति बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, व जमात ई इस्लामी, गठबंधन जैसा शत्रुता पूर्ण रवैया अपनाना चाहते हैं और न ही अवामी लिंग की तरह पूर्ण आत्म समर्पण की नीति का पालन करना चाहते हैं ऐसा लगता है कि बांग्लादेश को एक उदार लोकतंत्र में बदलने के बारे में विभिन्न प्रमुख राजनीतिक समूह के बीच व्यापक सहमति है जिसका भारत चीन या पाकिस्तान के समर्थन के बजाय अमेरिका के समर्थिक लोग जयादा लग रहे हैं

© 2025 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 April 2025, Revised: 09 May 2025, Accepted: 12 June 2025,

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने अपने आप को जमात ई इस्लाम से खुद को दूर करना शुरू कर दिया है और खुद को एक बार लोकतांत्रिक ताकत के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है।

बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाली वर्तमान चुनौतियां

बांग्लादेश में अगस्त का घटनाक्रम विवाद पूर्णरहा हसीना की जाने की कुछ घंटे बाद देश में अराजकता फैल गई अल्पसंख्यकों को परेशान किया गया अलकायदा नेताओं और कट्टरपंथी नेताओं द्वारा अगस्त मे देश को पुरी तरह अशांत कर दिया था अतरिम सरकार बनने के बाद बांग्लादेश शांति की ओर बढ़ा और अंत तक शांत हो गया अचानक मिली आजादी ने उन सभी शक्तियों को सक्रिय कर दिया जिससे शेख हसीना सरकार ने तानाशाही द्वारा दबा रखा था इसे बांग्लादेशी लोग दूसरी आजादी की सज्ञा भी देने लगे हैं इसी अराजकता का फायदा कुछ कटरपथी सगठन ने भी उठाया जिन्होंने अल्पसंख्यकों पर हमले किए तथा आंदोलन की आड़ में गरिक व रोमन देवी देवताओं और 1971 के मुक्ति संग्राम को दर्शाने वाली मूर्तियों को भी निशाना बनाया बनाकर तोड़ना शुरू कर दिया ओर कुछ इस्लामी मौलवी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भडकाऊ टिप्पणियां करके देश के नागरिकों को उसकाने का काम कर रहे थे एवं समाज को लड़ाने का काम कर रहे थे जिसका बांग्लादेश के छात्रों नागरिकों व समाज के प्रतिष्ठ व्यक्तियों यहां तक की आम लोगों द्वारा व्यापक आलोचना की गई

बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाली या देश का पूर्ण निर्माण

हसीना सरकार जब 2009 में सत्ता में आई तब आते ही जैसे सभी दक्षिण एशिया की देश करते है इसी प्रक्रिया में उन्होंने देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा लेने की प्रक्रिया को पूरी तरह अमल किया तथा विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डालना और विपक्ष की आवाज को पूरी तरह से दबाने का कार्य किया हसीना की सरकार ने किया यह लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुक ओर आम सहमति से निर्णय न लेना देश के नागरिकों के लिए बड़ी समस्या पेदा करने जेसा था देश पर में भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, मनी लांड्रिंग के अभूतपूर्व सतरो के बढोत्तरी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ओर मानवाधिकारों के हनन, ओर पिछले 16 वर्ष में मतदान के अधिकार से वचित किए जाने के खिलाफ शिकायतों को देश के नागरिक सहते रहे, 17 जुलाई 2024 को छात्रों ने कोटा सुधार आदौलन शुरू किया था उसे भेदभाव विरोधी आदोलन मे बदल दिया जिसमें सभी लोकतंत्र समर्थक लोग शामिल होते गये मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने आदोलन कारियों के साथ एक जड़ता दिखाते हुए सत्ताधारी सरकार की दमनकारी नीति की आलोचना की अंत में से एक हसीना सरकार को आदोलनकारियों के आगे झुकना पडा एवं इस्तिफा देना पडा। हसीना ने आंदोलन को दबाने के लिए 1000 से अधिक छात्रों की हत्या, इंटरनेट बंद अंतरराष्ट्रीय मीडिया में हिंसा को छुपाने का प्रयास किया लेकिन यह प्रयास निरर्थक साबित हुए। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास पर कब्जे के बाद शैख हसीना भारत भाग आई जिसस बांग्लादेश में मौलिक स्वतंत्रता और अधिकारों की बाहाली का मार्ग प्रशस्त हुआ।

नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता वाली अंतरिम सरकार का गठन किया गया जिसमें देश के प्रतिष्ठ व्यक्ति शामिल है जिसमें युवाओं को भी मौका दिया गया है अंतिम सरकार का समर्थन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भी किया है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को उम्मीद है कि अंतरिम सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देते हुए शांति और अमन बहाल करने में सफल होंगे 5 अगस्त के बाद अल्पसंख्यकों पर बहुत से हमले किए गए जिसमें से हिंदू मंदिरों को तोडा गया, अल्पसंख्यक समूह ने आरोप लगाया कि मंदिरों पर हमले में आवामी लिंग के लोग शामिल हैं कुंलिन सिंडिकेट के प्रभाव के कारण देश की आर्थिक दशा चिंता जनक है इन सभी सिंडिकेट को न्याय के कटघरे मे लाना चाहिए

बार–बार लग रहे चुनाव मे धाधली के आरोप के कारण व सरकार के साथ मिली भगत होने के कारण के चुनाव निष्पक्ष करना मुश्किल हो रहा है इसलिए चुनाव आयोग के पूर्ण गठन और जमीन स्तर पर चुनाव कराने के लिए तटस्थ अधिकारियों की नियुक्ति और मतदाता सूची को अपडेट करने जैसे कार्य पूरे किए जाने की आवश्यकता है

© 2025 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 April 2025, Revised: 09 May 2025, Accepted: 12 June 2025,

(June2025). वर्तमान परिप्रेक्ष्य व बांग्लादेश मे सत्ता परिवर्तन
International Journal of Economic Perspectives,*19*(06) 60-64
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का भारत पर प्रभाव

हसीना पर भारत का पूरा दाव अब उल्टा पड़ गया है यह भारत के इंटेलिजेंस की असफलता का प्रतीक है इसलिए एक क्रूर और अलोकप्रिय शासन का समर्थन करते रहे लेकिन अब समय आ गया है कि बांग्लादेश और भारत के लोग अतीत के बोझ को पीछे छोड़ दें और आपसी आर्थिक लाभ के लिए कम करें जिससे दोनों देशों के बीच टिकाऊ और बहू आयामी में संबंध बन सके वैसे भी बांग्लादेश अंदरुनी हालात ने भारत की चिंता बढ़ा दी है बांग्लादेश का ईतिहास गवाह है कि जब भी वहां गैरअवामी लिंग सरकार सत्ता में होती है तो भारतीय विरोधी गतिविधियां बढ़ जाती है क्योंकि बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पाकिस्तान की प्रमुख मुख्य समर्थक मानी जाती है जिसनें 1971 के मुक्ति संग्राम में भी पाकिस्तान का समर्थन किया था बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जमात ई ईस्लाम से नाम से जुड़े हुए कट्टरपंथी लोगों को जेल से बाहर निकलना शुरू कर दिया है यह जेल से बाहर आते ही भारतीय विरोधी गतिविधियों को निश्चित ही अंजाम देंगे, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो गया जिसके जिससे भारत को यह चिंता सताने लगी है कि पड़ोसी देश में फिर से विरोधी ताकतों को हवा मिलेगी भारत सिर्फ इस बात से चिंतित नहीं है कि बांग्लादेश में उसके खिलाफ अफवाहों को हथियार बनाया जा रहा है बल्कि जिस तरह से वहां के अधिकांश हिस्सों में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है वह भी चिंता का बड़ा कारण है जो सूचनाओं भारत को मिली है उनके मुताबिक पिछले दिनों आगामी लिंग के नेताओं और मीडिया पर हुए भीड़ के हमले से बचाने को लेकर सुना कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है उन्होंने लो और आर्डर का कार्य पुलिस का होने के कारण सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है इस स्थिति में भारतीय उच्च आयोग को भी अपने कार्यालय परिसंपत्तियों की चिंता सताने लगी है भारत के प्रमुख रणनीति विशेषज्ञ बरमा चेलानी ने भी कहा है की सेना समर्थित अतरिम सरकार प्रतिरोध की भावना के तहत उठाए जाने वाले कदमो या दुसरे गलत कामो को तो नहीं रोक पाई लेकिन राजनीतिक विरोधीयो, पत्रकारों, स्थानीय अधिकारियों अधिवक्ताओं और शिक्षाविदों को जेल में डाल रही है अल्पसंख्यकों पर हमले पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है उन्होंने बांग्लादेश में मानवाधिकार उल्लंघन और अल्पसंख्यकों पर हमले पर चुप्पी साथ रखी है इस बारे में अधिकारियों का कहना है कि पहले भी जब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्तित्व होती है तो उसका खम्याजा न सिर्फ भारत को ही बुगतना पड़ा है इसमें चीन की भी नाकामी साफ जलकती की दिखाई दे रही है शायद चीन को इस बात का एहसास भी होगा, अमेरिका ने जरूर हिम्मत दिखाई बांग्लादेश में जवाब देही स्वतंत्रता, लोकतंत्र मानवाधिकारों, के सुनिश्चित करने के बारे में मुखर रहा है

जिसका आंदोलनकारी और बांग्लादेशी लोगों ने भी समर्थन किया है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना को सत्ता से बेदखल करने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने या छात्र आंदोलन की ताकत को समझने में नई दिल्ली की नाकामी केवल हमारी कूटनीति का दुखद प्रतिबिंब है आने वाले समय में भारत को भी अपनी युवा शक्ति के बारे में संक्षेप रहने की प्रेरणा बांग्लादेशी युवा आंदोलन से देनी चाहिए और मोदी सरकार को भी समझना चाहिए की मुख्य विपक्षी पार्टियों को देश के हित में निर्णय में सहभागिता को महत्व दिया जाना चाहिए अगर हसीना की तरह मोदी भी विपक्षी पार्टियों को जेल में भरते रहेंगे तो वह समय दूर नहीं जब भारत में भी ऐसे हालात बन सकते हैं भारत की खुफिया एजेंसी इस आंदोलनकारी गतिविधियों के मूड को मापने में नाकाम रहीं भारत ने भी पिछले दो सालों में बांग्लादेश के राजनीतिक क्षितिज पर हसीना और अवामी लिंग की पकड़ कमजोर होते देखी है भारत ने चीन का मुकाबला को इस्लामी विकल्पों को दूर रखने के लिए आवामी लीग का समर्थन करना भारत सरकार की मजबूरी बना 1971 के मुक्ति संग्राम में नई दिल्ली की भूमिका के कारण हसीना और आवामी लिंग के भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी धनिष्ठा संबंध विकसित किए हैं अवामी लीग द्वारा बांग्लादेशी प्रवासियों और भारत में अल्पसंख्यक पर हमले के खिलाफ चुनाव प्रसार के दौरान ज्यादा आलोचना नहीं की गई हसीना ने इसका सार्वजनिक रूप से विरोध नहीं किया जब असम में एनआरसी को अपडेट किया गया तो चर्चा हुई विदेशियों को वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा तो उन्होंने भारत सरकार पर भरोसा करना चुना भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने कक्ष बांग्लादेश के देश मंत्री को विश्वास दिलाया कि एनआरसी एक एक घरेलू मुद्दा है इसका बांग्लादेश ढाका के संबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जब पसीना 2009 में अच्छे बहुमत के साथ सत्ता में आई तो उन्होंने पहला कदम यूनाइटेड लिबरल फ्रंट आफ असम के नेताओं को भारत के हवाले करना था उन्होंने बांग्लादेश में उत्तरी पूर्व अलगाववादी समूह को अपने देश में काम नहीं करने दिया हसीना के इस कदम से भारत सरकार और भारत के विपक्ष से दलों ने

© 2025 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 April 2025, Revised: 09 May 2025, Accepted: 12 June 2025,

बहुत सराहना की, हसीना सरकार का पतन का कूटनीतिक नतीजा मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है हसीना के 16 साल की राज के बाद बांग्लादेश दिशाहीन नजर आ रहा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त अतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व से भारत को थोड़ी राहत मिलेगी क्योंकि यूनुस की अंतरराष्ट्रीय छवि और अमेरिका यूरोपीय देशों के साथ काफी अच्छी पकड़ है उन्होंने अब तक भारत को सही संदेश भेजें हैं अल्पसंख्यक को आश्वासन दिया है कि उनकी रक्षा की जाएगी उन्होंने डिसेश्वरी मंदिर का दोरा भी किया और कानून व्यवस्था कि बहाली कि बात भी कि फिर भी दिल्ली अभी भी अनिश्चित है की बांग्लादेश की अंतरिम सरकार उन सब कार्यों पर अमल करेगी जो अवामी लिंग के द्वारा भारत से वादे किए गए थे।

शेख हसीना सरकार के संबंध कभी भी अमेरिका के साथ अच्छे नहीं रहे क्योंकि अमेरिका न्यू मलेशिया टाउनशिप पर अपना द्वीप बनाना चाहता था जिसका शेख हसीना सरकार ने विरोध कर दिया उसके बाद अमेरिका बाइडन प्रशासन के साथ उनके संबंध का कभी अच्छे नहीं रहे जब शेख हसीना पांच दिवसीय दौरे पर अमेरिका गई तो चार दिनों में ही उन्हें वापस लौटना पड़ा जिनका स्वागत करने के लिए कोई बड़ा अमेरिकी अधिकारी नहीं गया बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में अमेरिका और भारत हमेशा विपरीत विचार रहे हैं अमेरिका बांग्लादेश कैसे हालात के लिए हसीना सरकार को दोषी मानता है उसके विपरीत भारत हसीना सरकार का समर्थन करता है लेकिन इस मतभेद का भारत अमेरिका संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि चुनाव के बाद अमेरिका ने हसीना से बातचीत जारी रखी इसमें भारत की अहम भूमिका थी, भारत की चिंता बांग्लादेश के चुनाव के बाद होने वाली है क्योंकि बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनल लिस्ट पार्टी और उसके सहयोगियों को कट्टरपंथी समर्थक पाकिस्तान आई.एस.आई. के समर्थन के रूप में देखा जाता है।

जो भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है भारत को अभी बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा निकट भविष्य में समय बड़ा प्रतिकूल भी हो सकता है इसके अलावा जमात इस्लामी जो 1971 के मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान के समर्थक थे भारत के लिए बड़ी चुनौती होगी अंतरिम सरकार ने कुछ कट्टरपंथी संगठनों के प्रमुखों को जेलों से निकलना भी शुरू कर दिया है भारत का बांग्लादेश के साथ सबध सुधारना बड़ी चुनौती का सामना करना होगा क्योंकि भारत अवामी लीग को बड़ा समर्थन करता था जिसने बांग्लादेश में अपना वजूद खो दिया है जिससे आम लोगों का भारत के प्रति थोड़ा रोस व्याप्त है बांग्लादेश में हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के संबोधन से भी बड़ा रोस प्रकट किया है क्योंकि आंदोलन में मारे गए लोगों में युवाओं का कोई जिक्र नहीं है फिर भी अंतरिम सरकार ने मोदी से फोन पर बातचीत करके उससे संपर्क स्थापित करने की दिशा में पहला कदम उठाया है भारत में हसीना की मौजूदगी बड़ी चिंता की बात है क्योंकि अंतरिम सरकार ने हसीना के पास पासपोर्ट को रद्द कर दिया है और हसीना के खिलाफ 50 से ज्यादा कैसे लगा दिए हैं जिसमें से 40 तो हत्या से संबंधित है आंदोलन में मारे गए युवाओं के परिवार वाले हसीना को बांग्लादेश समर्पण की मांग कर रहे हैं इससे भारत सरकार बड़ी मुश्किल में है हसीना को बांग्लादेश को सोपना बाकी पड़ोसी देशों के लिए एक भयानक संदेश होगा जो कि भारत की प्रति दूसरे देशों में अविश्वास को प्रकट करेगा भारत के लिए अच्छा होगा हसीना जितनी जल्दी भारत से निकले भारत को अब नई सरकार के साथ नई शुरुआत करनी होगी और लोगों को विश्वास में लेना होगा

निष्कर्ष

बांग्लादेश में अगस्त 2024 का सत्ता परिवर्तन केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। यह आंदोलन युवाओं द्वारा शुरू हुआ और पूरे राष्ट्र में स्वतंत्रता, न्याय, और मानवाधिकारों के पक्ष में एक जनजागरण बन गया। शेख हसीना की तानाशाही प्रवृत्ति, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध, और विपक्ष के दमन ने वर्षों से जनता के भीतर असंतोष को जन्म दिया था, जो अंततः एक ऐतिहासिक विद्रोह के रूप में सामने आया। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में गठित अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। इस सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास बहाल करना, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और निष्पक्ष चुनाव कराना है। यदि यह सरकार इन लक्ष्यों को पूरा कर पाती है, तो बांग्लादेश एक सशक्त और उदार लोकतंत्र के रूप में उभर सकता है।

© 2025 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 April 2025, Revised: 09 May 2025, Accepted: 12 June 2025,

भारत के लिए यह परिदृश्य मिश्रित संकेत देता है। एक ओर, हसीना सरकार के पतन से उसकी दक्षिण एशिया नीति को झटका लगा है, वहीं दूसरी ओर यह अवसर भी है कि भारत नई बांग्लादेशी नेतृत्व के साथ लोकतांत्रिक, पारदर्शी और जनता–आधारित संबंध स्थापित करे। भविष्य में भारत को इस बात पर ध्यान देना होगा कि वह किसी एक दल या व्यक्ति पर निर्भर न रहकर जनता–आधारित कूटनीति को अपनाए।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बांग्लादेश में हालिया घटनाक्रम दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की नई चेतना का प्रतीक है। यह केवल बांग्लादेश के पुनर्निर्माण का नहीं, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप में लोकतांत्रिक आदर्शों के पुनः सशक्त होने का संकेत है। यदि यह परिवर्तन स्थायी शांति, समावेशी विकास और जनकल्याण की दिशा में आगे बढ़ता है, तो यह आंदोलन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत सिद्ध होगा।

संदर्भ

1. अहमद, मुनीर. बांग्लादेश का राजनीतिक इतिहास : स्वतंत्रता से लोकतंत्र तक. ढाका : बांग्ला प्रकाशन, 2022.
2. यूनुस, मोहम्मद. Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism. न्यूयॉर्क : PublicAffairs, 2008.
3. चेलानी, ब्रह्मा. Water: Asia's New Battleground. न्यू दिल्ली : हार्पर कॉलिन्स, 2021.
4. सरकार, रंजीत. दक्षिण एशिया की राजनीति और भारत के संबंध. कोलकाता : ओरिएंट लॉन्गमैन, 2020.
5. शर्मा, विवेक. भारत–बांग्लादेश संबंध : सीमाएं, सुरक्षा और रणनीति. नई दिल्ली : ज्ञान भारती प्रकाशन, 2023.
6. “Hasina’s Fall and Bangladesh’s Democratic Transition.” BBC Hindi, 6 Agusut, 2024, www.bbc.com/hindi/articles/bangladesh.political.change.2024.
7. सेन, दीपांकर. बांग्लादेशरू संघर्ष और स्थायित्व की खोज. ढाका : यूनिवर्सिटी प्रेस लिमिटेड, 2019.
8. अमेरिकी विदेश विभाग. Human Rights Report: Bangladesh 2024. वाशिंगटन डी.सी. : यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, 2024.
9. “Mohammad Yunus Forms Interim Government in Bangladesh.” The Guardian, 10 Agust, 2024, www.theguardian.com/world/2024/aug/10/bangladesh.interim. government-yunus.
10. “India’s Strategic Response to Bangladesh’s Political Crisis.” The Hindu, 12 August 2024, www.thehindu.com/news/international/india-bangladesh.political. transition.
11. घोष, आनंद. लोकतंत्र और छात्र आंदोलन : बांग्लादेश का अनुभव. कोलकाता : यूनिवर्सल बुक्स, 2025.

© 2025 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 April 2025, Revised: 09 May 2025, Accepted: 12 June 2025,